+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(केंद्रीय बजट 2024-25)

(September 2024)

(Part I)

TOPICS TO BE COVERED

- विकसित भारत की ओर
- सार्वजनिक वित्त और विकास: भारत की बजटीय प्राथमिकताओं का मूल्यांकन
- राजकोषीय माध्यम से भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

विकसित भारत की ओर:

- भारत 2047 तक 'विकसित भारत' बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय बजट 2024-25 विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करता है, जिसमें आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई है। बजट चार प्रमुख समूहों गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर केंद्रित है।

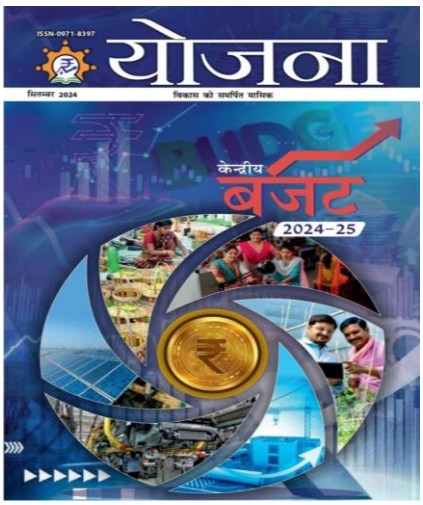

- समर्थ उद्योग, भारत 4.0 और PLI योजना जैसी पहलों का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना और 2025 तक GDP में इसकी हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है। स्वचालित और प्रक्रिया-संचालित विनिर्माण की ओर अग्रसर होना सही दिशा में एक कदम है, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में सक्षम बनाता है।
- एक व्यापक कौशल विकास पहल का लक्ष्य पांच साल की अवधि में लगभग 20 लाख युवाओं को सशक्त बनाना है। इस प्रयास में हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से 1,000 ITI का उन्नयन करना शामिल है, जो रोजगार और उद्योग की तत्परता बढ़ाने के लिए परिणाम-आधारित प्रशिक्षण को प्राथमिकता देता है।

- सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है और इसमें वृद्धि की संभावना है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों और संस्थागत ढांचों पर ध्यान केंद्रित करने से इस क्षेत्र के विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया है जिससे सेवा क्षेत्र हाल के वर्षों में दोहरे अंकों की वृद्धि कर रहा है।
- केंद्रीय बजट 2024-25 इन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्धता को फिर मजबूत करता है, जिसमें विनिर्माण और सेवाओं सहित प्राथमिकता वाले नौ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट का उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देना है।
- केंद्रीय बजट 2024-25 विनिर्माण, सेवाओं और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के आर्थिक विकास के लिए एक आशाजनक मार्ग तैयार करता है। इस पहल में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने की क्षमता है लेकिन उनकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन और संभावित बाधाओं को दूर करने पर निर्भर करती है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सार्वजनिक वित्त और विकास: भारत की बजटीय प्राथमिकताओं का मूल्यांकन

परिचय:

- 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश किया, जो 'गरीब', 'महिला', 'युवा' और 'अन्नदाता' पर केंद्रित है। बजट का उद्देश्य रोजगार सृजन, कौशल विकास, MSME और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना, क्षेत्रीय विकास को संतुलित करना और कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है।

- इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जोर दिया, जिनमें रोजगार, कौशल विकास, MSME, कृषि, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के अवसर, और क्षेत्रीय विकास आदि शामिल हैं।

प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और लचीलापन

- कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कुल रोजगार में 42.3 प्रतिशत का और देश के सकल घरेलू उत्पाद में 18.2 प्रतिशत का योगदान करती है।
- इसके विशेष महत्व को समझते हुए बजट में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाने के लिए कृषि क्षेत्र के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रचुर आवंटन किया गया है। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए घोषित प्रमुख पहल निम्नलिखित हैं:
- **कृषि अनुसंधान में बदलावः** कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-अनुकूल फसलों के विकास के लिए सरकार ने कृषि अनुसंधान में व्यापक सुधार का निर्णय लिया है। इस बजट में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को कृषि अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव है, जिससे 32 फसलों की 109 नई, उच्च उपज वाली और जलवायु-अनुकूल किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जा सकें।

- **प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहनः** भारतीय प्राकृतिक कृषि बगैर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग के देसी गायों और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। यह जलवायु-अनुकूल, लागत प्रभावी पद्धति है। बजट में अगले दो वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने, 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने, और प्रमाणीकरण व ब्रांडिंग के माध्यम से किसानों की सहायता का प्रस्ताव है।
- **दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरताः** दलहन पर्यावरण के अनुकूल और पोषण और स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले हैं। भारत वर्तमान में 4.4 मिलियन टन दालों का आयात करता है। इसी तरह खाद्य तेल के लिए भी आयात पर बहुत अधिक निर्भरता है। बजट में इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करके दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया गया है।
- **सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाः** फलों और सब्जियों के 256 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। परन्तु इससे जड़ी अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त बाजार संपर्कों के कारण कटाई के बाद काफी नुकसान होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए वित्त

मंत्री ने प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित करने और सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPO), सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की।

- **कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार के लिए अभिनव, किसान-केंद्रित समाधानों और सेवाओं के विकास को सक्षम करेगी। यह फसल के लिए योजना निर्धारण, फसल आकलन और बाजार की जानकारी में सहायता करने और कृषि तकनीक उद्योग और स्टार्टअप के विकास में सहायता करेगा। बजट में केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में चालू वित्त वर्ष में 400 जिलों में खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण करेगी।
- **झींगा उत्पादन और निर्यात पर बल:** इन उपायों के अलावा वित्त मंत्री ने झींगा उत्पादन और निर्यात पर सरकार द्वारा बल दिए जाने की घोषणा की।

प्राथमिकता 2: रोजगार और कौसल विकास

- भारत के पास बेहतर जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति है लेकिन इस क्षमता को साकार करने के लिए कौशल बेमेलता, रोजगार अवसरों में क्षेत्रीय असमानता,

अल्परोजगार और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। ऐसे में रोजगार और कौशल विकास बजट के केंद्रीय उद्देश्य हैं।

- बजट में रोजगार और कौसल विकास के लिए 2 लाख करोड़ के आवंटन के साथ पांच योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गयी है, जिसका लक्ष्य पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करना है।
- **रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-क (पहली बार काम करने वालों के लिए):** यह 2.1 करोड़ युवाओं को लक्षित है जो 1 लाख प्रतिमाह से कम वेतन के साथ नए कार्यबल में प्रवेश करते हैं।
- **रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-ख (विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन):** यह योजना 30 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में नए EPFO कर्मचारियों की भर्ती को बढ़ावा देती है।
- **रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-ग (नियोक्ताओं को सहायता):** इस योजना से 50 लाख लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलने और सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार मिलने की अपेक्षा है।
- **कौशल विकास और ITI को अपग्रेड करने के लिए नई योजना:**
  - ➢ प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 20 लाख युवाओं को पांच वर्ष की अवधि में कौशल प्रदान करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) शुरू की जाएगी।

➢ इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और उद्योग क्रमशः 30,000 करोड़ रुपये, 20,000 करोड़ रुपये और 10,000 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।

➢ यह योजना उद्योग के सहयोग के साथ हब-एंड-स्पोक मॉडल के अनुरूप 1,000 ITI को अपग्रेड करेंगी, पाठ्यक्रम सामग्री को उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ेगी और उभरती मांगों के लिए नए पाठ्यक्रम लाएगी।

- **शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप:** प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के माध्यम से पांच वर्षों में 21-24 वर्ष की आयु के एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करेगी। इंटर्न को एक साल के लिए 5,000 मासिक भत्ता मिलेगा। कंपनियां मासिक 6,000 का योगदान देगी और CSR फंड के जरिए प्रशिक्षण लागत वहन करेंगी।
- **महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी सुनिश्चित करना:** वित्त मंत्री ने महिलाओं की कार्यबल में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रेच के निर्माण के साथ-साथ कौशल विकास ऋण और शिक्षा ऋण योजनाओं की घोषणा की।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

- इस वर्ष का बजट विशेष रूप से किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के व्यापक और समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस दिशा में प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
- **सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए संतृप्त दृष्टिकोणः** सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ मिले।
- **पूर्वोदयः** सांस्कृतिक परंपराओं और संसाधनों से समृद्ध भारत के पूर्वी क्षेत्र में 'पूर्वोदय' योजना का उद्देश्य मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों का विकास करना है जिससे इस क्षेत्र को विकसित भारत के लिए एक इंजन में बदला जा सके।
- **महिलाओं के नेतृत्व में विकासः** बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन आर्थिक विकास में उनकी भूमिका पर बल देता है।
- **प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानः** आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए सरकार आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी

जिलों में आदिवासी परिवारों को शामिल करते हुए यह पहल शुरू करेगी। इस पहल से 63,000 गांवों में पांच करोड़ से अधिक आदिवासी लोग लाभान्वित होंगे।

- **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास के लिए वित्तपोषण में वृद्धि:**
  - ➢ बजट में शिक्षा के लिए आवंटन 12 प्रतिशत बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ कर दिया गया है।
  - ➢ स्वास्थ्य सेवा के लिए वित्तपोषण 15 प्रतिशत बढ़ा कर 3.8 लाख करोड़ कर दिया गया है।
  - ➢ आवास की जरूरतों के लिए केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण में सहायता करेगी।

प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवा क्षेत्र

- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
- **MSME के लिए ऋण गारंटी योजनाः** सरकार MSME को बिना किसी कोलेटरल की गारंटी के मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करेगी। इससे छोटे व्यवसायों का विस्तार होगा और अधिक रोजगार सृजित होंगे।

- **MSME ऋण के लिए नया मूल्यांकन मॉडलः** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पारंपरिक मानदंडों के बजाय MSME के डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर एक ऋण मूल्यांकन मॉडल विकसित करेंगे जिससे ऋण प्राप्ति में सुधार होगा।
- **TReDS में ऑनबोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायराः** बजट ने 'व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)' प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ कर दिया गया है जिससे MSME के लिए कार्यशील पूंजी अनलॉक हो सके। TReDS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो MSME को उनकी प्राप्तियों को नकदी में परिवर्तित करके कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
- **विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजनाएं:** MSME को बढ़ावा देने के अलावा बजट में विनिर्माण और सेवाओं को बढ़ावा देने कई पहल शामिल हैं:
  - ➢ **औद्योगिक पार्कः** सरकार राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 शहरों में पूर्ण बुनियादी ढांचे के साथ निवेश के लिए तैयार 'प्लग एंड प्लें' औद्योगिक पार्क विकसित करेगी।
  - ➢ **औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराये के आवासः** औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास-प्रकार की सुविधा के साथ किराये के आवास को पीपीपी मोड में सुगम बनाया जाएगा।

- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) अनुप्रयोगः** ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, रसद, MSME, सेवा वितरण और शहरी शासन जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता, व्यापार के अवसरों और नवाचार को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर DPI अनुप्रयोग विकसित किए जाएंगे।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाः** बजट में PLI योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और प्रमुख उद्योगों में रोजगार पैदा करना है।
- **स्टार्टअप को बढ़ावा देनाः** स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए बजट में सभी वर्गों के निवेशकों पर 'एंजेल टैक्स' को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

प्राथमिकता 5: शहरी विकास

- शहरी विकास बजट की एक प्रमुख प्राथमिकता है। सरकार की बजट में प्रस्तावित पहलों का उद्देश्य शहरों को विकास केंद्रों के रूप में विकसित करना, रोजगार सृजित करना, शहरी स्थिरता को बढ़ाना और शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
- **विकास केन्द्र के रूप में शहर:** राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार शहरों को विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने में मदद करेगी।

- **शहरों का रचनात्मक पुनर्विकासः** सरकार मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सक्षम नीतियों, बाजार-आधारित तंत्रों और विनियमों के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी।
- **पारगमन-उन्मुख विकासः** 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के पारगमन-उन्मुख विकास के लिए विकास योजनाएं, कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीतियां तैयार की जाएगी।
- **शहरी आवासः** सरकार अगले पांच वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए **एक करोड़ घर** बनाने के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश करेगी। इसमें किफायती दरों पर ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी शामिल है।
- **जल आपूर्ति और स्वच्छताः** 100 बड़े शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा देगी।

प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा

- आर्थिक विकास को बनाए रखने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बजट में घोषित प्रमुख पहल हैं:
- **ऊर्जा संक्रमणः** सरकार ऊर्जा संक्रमण पथ पर एक नीति लाएगी जो रोजगार, विकास और पर्यावरणीय सततता को समावेशित करेगी। इस बजट में सौर, पवन

और हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

- **पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाः** इस योजना का उद्देश्य छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है जिससे करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 6,250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी स्टोरेज नीतिः** विद्युत भंडारण के लिए 'पंप भंडारण परियोजनाओं' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नीति तैयार की जाएगी जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को उसके 'परिवर्तनशील' और अस्थायी प्रकृति के साथ एकीकृत करने में सुविधा होगी।
- **मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान एवं विकासः** सरकार 'भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर' के अनुसंधान एवं विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।
- **उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांटः** भारत ने 'उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (AUSC)' थर्मल पावर प्लांट के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है। NTPC और VHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में AUSC प्रौद्योगिकी का उपयोग

करके 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्राथमिकता 7: बुनियादी ढांचा

- बुनियादी ढांचे में निवेश का रोजगार गुणक प्रभाव बहुत अधिक होता है, उत्पादकता में सुधार होता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। बजट में बुनियादी ढांचे को लेकर निम्नलिखित पहल शामिल हैं:
- **केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेशः**
  - ➢ केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत होगा।
  - ➢ राज्य सरकारों को भी पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ तक पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **बुनियादी ढांचे में निजी निवेशः** केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, सक्षम नीतियों और बाजार आधारित वित्तपोषण ढांचे के माध्यम से बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देगी।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा।
- **पर्यटन अवसंरचना:** केंद्र सरकार प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने में राज्य सरकारों की सहायता करेगी। पर्यटन विकास से रोजगार सृजित होंगे, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर खुलेंगे।

प्राथमिकता 8: नवाचार, अनुसंधान और विकास

- अनुसंधान और विकास (R&D) और नवाचार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- इसके अतिरिक्त, बजट में 1 लाख करोड़ का वित्तपोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाने का प्रस्ताव है।
- इसके अलावा, अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार

- अगली पीढ़ी के सुधारों का उद्देश्य अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना है। केंद्र सरकार आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को परिभाषित करने और सुधारों की अगली लहर को आगे बढ़ाने के लिए एक 'आर्थिक नीति ढांचा' तैयार करेंगी।
- इन सुधारों में राज्य सरकारें की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, राज्यों को सुधारों के तेजी से क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 'भूमि-संबंधी सुधारों' के लिए राज्यों को 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण का एक हिस्सा आवंटित करने का प्रस्ताव है।
- बजट में FDI और विदेशी निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित की जा सके, निवेश को प्राथमिकता दी जा सके और विदेशी लेनदेन के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

राजकोषीय माध्यम से भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना:

परिचय:

- भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परिवर्तनकारी, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसमें भौतिक, सामाजिक, वित्तीय तथा डिजिटल बुनियादी ढांचा शामिल है।
- विभिन्न अध्ययनों में पाया गया कि निवेश खर्च में 1 प्रतिशत की वृद्धि भारत में सकल घरेलू उत्पाद को 1.0 से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत तक कर सकती है, जिसका सीधा प्रभाव रोजगार सृजन और सतत विकास पर पड़ता है।

- इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि परिवहन, ऊर्जा तथा शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश उनके अधिक गुणक प्रभावों के कारण व्यवस्थित और तेज गति से विकास को बढ़ावा देता है। ऐसे में जाहिर है, मौजूदा बजट में इन क्षेत्रों और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों के लिए धन आवंटित किया गया है।

प्रमुख बुनियादी ढांचा पहल और आवंटन 2024-25:

- बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- यह राशि GDP का 3.4 प्रतिशत है, जो पिछले कुछ दशकों में अब तक का सबसे अधिक है। यह वर्तमान जरूरतों को पूरा करने और तेजी से विकसित हो रहे भारत की भविष्य की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की सकारात्मक मंशा को दर्शाता है।
- पिछले पांच वर्षों के बुनियादी ढांचे पर निवेश के लिए आवंटन में लगातार प्रगति दिखाई देती है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ता को दर्शाता है।

भौतिक संपर्क अवसंरचना:

- भारत में भौतिक संपर्क और अवसंरचना विकास को बढ़ाने के लिए बजट प्रावधानों में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में निवेश शामिल है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत, एकीकृत और पारस्परिक रूप से सहायक परिवहन व्यवस्था का निर्माण करना है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सड़क मार्गः

- सड़क नेटवर्क के उन्नयन ने परिवर्तनशील और कुशल बुनियादी ढांचे को जन्म दिया है। इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय रूप से सबसे अधिक निजी निवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण को आकर्षित किया है।
- देश भर में मजबूत सड़क नेटवर्क बनाने के लिए सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के लिए बजट में 2.78 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

रेलवेः

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क समेटे हुए है। रेलवे क्षेत्र में काफी अधिक निवेश किया जा रहा है, क्योंकि यह लोकोमोटिव और वैगनों दोनों के लिए अधिकतम उत्पादन के साथ विभिन्न अवसरों को खोलता है।
- सरकार के द्वारा रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में स्वच्छता प्रदान करने के लिए कई पहल की गई हैं। यातायात गलियारों, ऊर्जा गलियारों, खनिज तथा सीमेंट गलियारों और रेल सागर गलियारों जैसे क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।

- बजट 2024-25 में रेलवे विकास के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है और इससे विकास पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

जलमार्गः

- आर्थिक विकास को बढ़ाने और स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, स्मार्ट जल प्रौद्योगिकी तथा बुनियादी ढांचे में निवेश, बढ़ते व्यापार को पूरा करने और वैश्विक क्षेत्र में भारत की समुद्री प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं की बढ़ती संख्या ने 'पीएम गति शक्ति' राष्ट्रीय मास्टर प्लान और 'सागरमाला' राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाया है।

वायुमार्गः

- विमानन क्षेत्र में निवेश वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। सरकार ने समूचे भारत में हवाई अड्डों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 की अवधि के लिए 26,000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है।

- विमानों को पट्टे पर देने और शिक्षा, कृषि आपदा प्रबंधन तथा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने वाले ड्रोन के उपयोग के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं।

अंतरिक्ष अवसंरचना:

- भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अंतरिक्ष अवसंरचना के लिए विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एक ओर वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और दूसरी ओर कई सफल मिशनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा तथा वैज्ञानिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए उत्सुक है।
- बजट 2024-25 में, सरकार ने अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना तक विस्तारित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के उद्यम पूंजी कोष का प्रस्ताव दिया है।

डिजिटल अवसंरचना:

- एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निवेश, निश्चित रूप से भारत के 'डिजिटल इंडिया', 'फिनटेक नेशन' और 'स्टार्टअप इंडिया' के उद्देश्यों को प्राप्त करने के द्वार खोलता है।
- भारत सरकार ने बजट में इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया है। डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सूचना

प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्रों के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।

- भारत सरकार ने पीएम गतिशक्ति, भुवन, भारतमैप्स, सिंगल विंडो सिस्टम, परिवेश पोर्टल, नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफार्म, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति), इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड (IIG) आदि जैसी कई कुशल बुनियादी ढांचा योजनाएं शुरू की हैं।
- सरकार 'भारत में एआई और भारत के लिए एआई' के तहत समावेश, नवाचार और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एआई को शामिल कर रही है।

ऊर्जा अवसंरचना:

- ऊर्जा के अधिक उपयोग और इसके परिणामों के प्रभाव को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य-2030 को पूरा करने के वास्ते ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए राशि आवंटित की जाती रही है।
- चूंकि इस क्षेत्र में निवेश करने से आर्थिक विकास, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सतत विकास को बढ़ावा देने के विभिन्न अवसर खुलते हैं। इसके बुनियादी ढांचा विकास में इस पर निर्भर विभिन्न क्षेत्रों के साथ सहसंबंध और उनका विकास भी शामिल होता है।

- इस क्षेत्र से 2024 और 2030 के बीच भारत में 30.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है, जिसमें देश के पारंपरिक स्रोतों से गैर-जीवाश्म ईंधन के उपयोग की ओर बढ़ने की आकांक्षा है।

अन्य बुनियादी ढांचा पहल:

- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए:** भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 2.66 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो पिछले वर्ष के बजट से लगभग 12 प्रतिशत अधिक है।
- **'प्रधानमंत्री आवास योजना':**
  - ➢ 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए तीन करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है।
  - ➢ 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (शहरी 2.0) के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इसमें अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चरण-4 की शुरुआत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए की जाएगी।
- **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम:** त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए 11,500 करोड़ रुपये की लागत से वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
- **'पूर्वोदय' योजना:** सरकार ने देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 'पूर्वोदय' नामक योजना तैयार की है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों को खोलना शामिल होगा, ताकि इस क्षेत्र को 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने का वाहक बनाया जा सके।

आगे की राह और 2047 तक भारत का भविष्य:

- बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत की विकास यात्रा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में नया मोड़ लेगी; और 'विकसित भारत-2047' तक भारत को 'विकसित राष्ट्र' बनाने में मदद करेगी, जो पूर्ण रूप से समग्र और सतत विकास का वादा करती है।

- केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त निवेश के प्रावधान किए हैं। बुनियादी ढांचे पर खर्च और सकल घरेलू उत्पाद के बीच सकारात्मक सहसंबंध वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में राजकोषीय समेकन उद्देश्यों और लक्ष्यों से समझौता किए बिना बुनियादी ढांचे के प्रावधान में वृद्धि को रेखांकित करता है।
- यह एक तथ्य है कि स्वाभाविक रूप से बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास से कुछ पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेंगे और राष्ट्र के लिए चुनौतियां पैदा होने की संभावना है। इसलिए, जन समाज के हित तथा पृथ्वी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं समय की मांग हैं।
- इसके अलावा, नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवर्धित बुनियादी ढांचागत बजट के परिणामस्वरूप सामाजिक-आर्थिक विकास के लाभ निचले तबकों और अंतिम छोर तक नागरिकों तक पहुंचें। यह सार्वजनिक नीतिगत पहल और सुशासन से सुनिश्चित किया जा सकता है।
- इन बहुविध लेकिन विकासोन्मुख उपायों के साथ भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए आगे बढ़ सकता है।